1. INtel AI (INAI) पहल का शुभारम्भ

- 13 अक्टूबर, 2020 को आयोजित वर्चुअल समिट **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2020** के दौरान, **तेलंगाना सरकार इंटेल इंडिया** के साथ मिलकर **हैदराबाद** में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान केंद्र शुरू करेगी । अनुसंधान केंद्र अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद (IIIT-H) और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PHFI) के साथ शुरू किया जायेगा । केंद्र का नाम INAI रखा गया है।

- INAI, AI को भारतीय संदर्भ में जनसंख्या पैमाने की समस्याओं पर लागू करने की एक पहल है, जिसमें मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा और स्मार्ट मोबिलिटी सेगमेंट में चुनौतियों को पहचानने और हल करने पर ध्यान केंद्रित करना है।

- **ध्यान दें: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस** (AI): यह मशीन कार्य को ऐतिहासिक दृष्टि से मानव बुद्धिमत्ता के कार्य को पूरा करने का वर्णन करता है। यह मशीन सीखने, पैटर्न मान्यता, बड़ा डेटा, तंत्रिका नेटवर्क, स्वयं एल्गोरिदम आदि जैसी तकनीकों को शामिल करता हैं।

- NITI Aayog ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति प्रकाशित की है जिसमें उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पांच मुख्य क्षेत्रों (**हेल्थकेयर, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट सिटीज और इन्फ्रास्ट्रक्चर, बैंडिकूट रोबोट**) की पहचान की है। **वी कामकोटि** की अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स समिति विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए AI का लाभ उठाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए गठित की गई।

2. भारत एससीओ के सातवें न्याय मंत्रियों की बैठक में शामिल होगा

- केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद शंघाई सहयोग संगठन के न्याय के मंत्रियों की सातवीं बैठक में शामिल होंगे।

- बैठक के दौरान मंत्री विवाद समाधान तंत्र, फोरेंसिक गतिविधियों और अन्य कानूनी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर ज्ञान साझा करेंगे। साथ ही, मंत्री कानूनी सेवाओं और फोरेंसिक गतिविधियों के विशेषज्ञों के कार्य समूहों की कार्य योजना पर चर्चा करेंगे।

Gradeup Bihar State Exams Green Card Subscription
(BPSC, Bihar SI, Bihar SSC etc.)
Get unlimited access to all 40+ mock tests

एससीओ के बारे में तथ्य:

- शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) या शंघाई पैक्ट एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है।
- **गठन:** 15 जून 2001
- **सदस्य:** चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान।
- **मुख्यालय:** बीजिंग, चीन

3. हरियाणा सरकार ने "ऑन व्हील्स लैब" का शुभारंभ किया

- यह राज्य में पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करेगा। हरियाणा राज्य की जल गुणवत्ता मुख्य रूप से लोहे, फ्लोराइड, नाइट्रेट और क्षारीयता से प्रभावित है। यह एक मोबाइल प्रयोगशाला है जिसे **जल जीवन मिशन** के अंतर्गत शुरु किया गया।
- मोबाइल प्रयोगशाला कठोरता, क्षारीयता, क्लोरीन, जस्ता, मैलापन, नाइट्रेट, PH और अन्य सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षणों के लिए परीक्षण करेगी।

जल जीवन मिशन के बारे में तथ्य:

- जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्यतक सभी ग्रामीण घरों में **2024** तक पाइप पेयजल उपलब्ध कराना है ।
- कार्यान्वयन के लिए **जल शक्ति मंत्रालय** को नोडल मंत्रालय बनाया गया।
- जल जीवन मिशन (JJM) 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घर में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है।
- गोवा राज्य सभी घरों में स्वच्छ पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

Gradeup Bihar State Exams Green Card Subscription
(BPSC, Bihar SI, Bihar SSC etc.)
Get unlimited access to all 40+ mock tests

4. **एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा**

एफएटीएफ (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) के बारे में:

- यह 1989 में स्थापित **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन** के तहत एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसक मुख्यालय **पेरिस** में है।
- एफएटीएफ का मुख्य उद्देश्य मानक तय करना और धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।
- **सदस्य देश**: 37 देश (भारत सहित।

एफएटीएफ की दो सूचियाँ:

- **ग्रे सूची**: वे देश जिन्हें आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित माना जाता है। यह देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि वह ब्लैकलिस्ट में दर्ज हो सकता है।
- **काली सूची**: वे देश जिन्हें गैर-सहकारी देश या क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, उन्हें काली सूची में डाल दिया जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं। एफएटीएफ प्रविष्टियों को जोड़ने या हटाने के लिए नियमित रूप से ब्लैकलिस्ट को संशोधित करता है।

5. **केरल सार्वजनिक शिक्षा में पहला डिजिटल राज्य बन गया**

- केरल राज्य सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया।

केरल के बारे में तथ्य:

- देश में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में है।
- **राजधानी:**तिरुवनंतपुरम

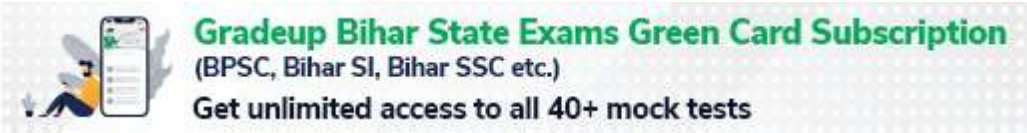

- **मुख्यमंत्री:** पिनाराई विजयन
- **राज्यपाल:** आरिफ मोहम्मद खान

6. जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने छत्तीसगढ़ एमएफपी संघ और आईआईटी, कानपुर के सहयोग से "आदिवासियों के लिए टेक" पहल शुरू किया

- "टेक फॉर ट्राइबल्स" शीर्षक कार्यक्रम का उद्देश्य वन धन केंद्रों (वीडीवीके) के द्वारा संचालित होने वाले एसएचजी के माध्यम से उद्यमिता विकास, सॉफ्ट स्किल, आईटी और व्यवसाय विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ आदिवासियों के समग्र विकास का उद्देश्य है।

वान धन विकास केन्द्रों के बारे में

- इस पहल का उद्देश्य जनजातीय इकट्ठाकर्ताओं और कारीगरों के एमएफपी केंद्रित आजीविका विकास को बढ़ावा देना है।
- यह जमीनी स्तर पर एमएफपी के अलावा प्राथमिक स्तर मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देकर आदिवासी समुदाय को बढ़ावा देता है।
- महत्व: इस पहल के माध्यम से, गैर-इमारती लकड़ी वन उपज के मूल्य श्रृंखला में आदिवासियों की हिस्सेदारी वर्तमान 20% से बढ़कर लगभग 60% होने की उम्मीद है।
- इस योजना को केंद्रीय स्तर पर नोडल विभाग के रूप में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के माध्यम से और राष्ट्रीय स्तर पर **ट्राइफेड (जनजातीय सहकारी विपणन संघ)** को नोडल एजेंसी के रूप में लागू किया जाएगा।

7. राष्ट्रीय कामधेनु आयोग (आरकेए) ने इस वर्ष दीपावली त्योहार के अवसर पर "कामधेनु दीपावली अभियान" मनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया।

- इस अभियान के माध्यम से, आरकेए इस दिवाली महोत्सव के दौरान गाय के गोबर / पंचगव्य उत्पादों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देगा।
- गोबर आधारित दीयों, मोमबत्तियों, धूप, अगरबत्ती, शुभ-लाभ, स्वस्तिक, समरणी, हार्डबोर्ड, वॉल-पीस, पेपर-वेट, हवन सामग्री, भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों के निर्माण की पहल कर चुका है।

Gradeup Bihar State Exams Green Card Subscription
(BPSC, Bihar SI, Bihar SSC etc.)
Get unlimited access to all 40+ mock tests

राष्ट्रीय कामधेनु आयोग (आरकेए) के बारे में:

- गायों और उनकी संतानों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास और पशु विकास कार्यक्रमों को दिशा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय काम धेनु आयोग (आरकेए) का गठन किया गया है।

8. **नेचिपु (NECHIPHU) सुरंग**

- केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में बालीपारा-चारुदर-तवांग (बीसीटी) मार्ग पर नेचिपु सुरंग का शिलान्यास किया।
- इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा किया जाएगा।

BRO के बारे में तथ्य:

- **आदर्श वाक्य:** भावार्थश्रमण सर्व साधम (कठिन परिश्रम से सब कुछ प्राप्त होता है)
- **स्थापित:**7 मई 1960
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली
- **महानिदेशक:** लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह
- **अंतर्गत:** रक्षा मंत्रालय

9. **केंद्रीय वित्त मंत्री ने खपत की मांग पैदा करने और अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के उपायों के दो सेटों की घोषणा की।**

- **यात्रा अवकाश रियायत (एलटीसी) कैश वाउचर योजना**, सरकार ने 2018-21 के दौरान एक एलटीसी के बदले में कर्मचारियों को नकद भुगतान देने का निर्णय लिया है, जिसमें एलटीसी के छुट्टी के नकदीकरण पर पूर्ण भुगतान और ब्याज मुक्त भुकतान 3 फ्लैट दर स्लैब पात्रता की श्रेणी के आधार पर दिए जाएंगे।
- **विशेष महोत्सव अग्रिम योजना** जो गैर-राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, को राजपत्रित कर्मचारियों के लिए भी एक बार के उपाय के रूप में लागू किया जा रहा है। सभी

Gradeup Bihar State Exams Green Card Subscription
(BPSC, Bihar SI, Bihar SSC etc.)
Get unlimited access to all 40+ mock tests

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब प्रीपेड RuPay कार्ड के माध्यम से रु10,000 की ब्याज मुक्त अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं जिसे 31 मार्च, 2021 तक खर्च किया जाएगा।

- **राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय प्रोत्साहन:** 50 साल का ब्याज रहित लोन राज्यों को 12 हजार करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के लिए दिया जाएगा। (राज्यों को दिए गए ब्याज-मुक्त ऋण 31 मार्च, 2021 तक खर्च किए जाने हैं)

10. **14 अक्टूबर, विश्व मानक दिवस**

- इस दिवस की **थीम "मानकों के साथ ग्रह की रक्षा"** है।

- प्रत्येक वर्ष, आईएसओ, आईईसी और आईटीयू के सदस्य विश्व मानक दिवस मनाते हैं, जो दुनिया भर के हजारों विशेषज्ञों के सहयोगात्मक प्रयासों को श्रद्धांजलि देने का एक माध्यम है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित होने वाले स्वैच्छिक तकनीकी समझौतों को विकसित करते हैं।

- **भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में**

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत काम करने वाला भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह बीआईएस अधिनियम, 1986 द्वारा स्थापित है।

Gradeup Bihar State Exams Green Card Subscription
(BPSC, Bihar SI, Bihar SSC etc.)
Get unlimited access to all 40+ mock tests